(ख) जी, हां । पड़ौसी राज्यों से कच्चे पानी की अनुपलब्धता के कारण दिल्ली की जलपूर्ति में वृद्धि करने में बाधा पड़ी ।

(ग) दिल्ली की जलपूर्ति में वृद्धि करने के लिए कुछ दीर्घकालिक योजनाएं जो चल रही हैं, के अलावा तत्काल प्रकृति के निम्नलिखित कार्य आरम्भ किये गये ;

(i) 120 लाख गैलन प्रतिदिन पानी प्राप्त करने के लिए अलीपुर में तीस रैनी कुंओं का निर्माण । मयूर विहार में एक रैनी कुंए का निर्माण कार्य पूर्ण होने वाला है । इससे 30 लाख गैलन प्रतिदिन पानी प्राप्त होने की आशा है ।

(ii) यमुना नदी के तट पर पांच अतिरिक्त रैनी कुंओं का निर्माण करने की कार्यवाही भी की गई है । इन पांच अतिरिक्त रैनी कुंओं से लगभग 200 लाख गैलन पानी प्रतिदिन प्राप्त होगा ।

(iii) वजीराबाद में प्रतिदिन 400 लाख गैलन जल-शोधन संयंत्र का निर्माण ।

(iv) ओखला में प्रतिदिन 120 लाख गैलन जल-शोधन संयंत्र का निर्माण ।

कुल मिलाकर इनसे प्रतिदिन 700 लाख गैलन से अधिक पानी प्राप्त होगा ।

दिल्ली में जाली राशन कार्ड

1316. **श्री शरद यादव :** क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में जाली राशन कार्डों के माध्यम से राशन लिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो 1986-87 और 1987-88 के दौरान जाली राशन कार्डों के कितने मामले पकड़े गए; और

(ग) सरकार ने दिल्ली में जाली राशन कार्डों का पता लगाने के लिए अब तक क्या प्रयास किए हैं ?

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में उपमंत्री (श्री डी०एल० डेठा) : (क) से (ग) दिल्ली प्रशासन ने कहा है कि उनके द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए हर कोशिश की जाती है कि राशन केवल वास्तविक खाद्य कार्डधारियों द्वारा ही लिए जाएं । यह कार्य राशनकार्ड जारी करते समय सत्यापन करने की प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, तथापि, जाली राशन कार्ड समाप्त करने हेतु कारवाई या तो शिकायतों के आधार पर की जाती है अथवा विशेष अभियानों/जांचों के माध्यम से की जाती है ।

जाली यूनिटों का पता लगाने के लिए 25-12-1985 से 27-3-1987 तक एक विशेष अभियान चलाया गया था, जिसके फलस्वरूप 5,65,567 यूनिटों को समाप्त कर दिया गया था ।

Elections to local bodies

1317. SHRI ALADI ARUNA *alias* V. ARUNACHALAM: Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether there is any proposal under Government's consideration to introduce statutory changes to ensure regular elections to all the local bodies; and

(b) if so, by when there are likely to be introduced in Parliament?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI DALBIR SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.